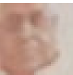

वाली बैंक की मोदी सरकार की नजरों के सामने देश की साइबर सुरक्षा व्यवस्था [illegible] है. उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट्स के रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले साल लगभग 72 फीसदी कंपनियों पर साइबर अटैक हुआ. 63 फीसदी कंपनियों को आर्थिक नुकसान सहना पड़ा है. देश में 2014 473 व 2015 में 11467 साइबर अपराध के केस दर्ज हुए हैं. इस साइबर से बचाने की कोई कार्ययोजना या विशेष कार्यक्रम मोदी सरकार ने अब तक के समक्ष नहीं पेश किया.

सानों के लिए आयेगा अलग बजट : राधामोहन

मस्तीपुर. देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद को नमन करते हुए केंद्रीय कृषि राधामोहन सिंह ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस उसी महान विभूति के जन्म दिवस पर पड़ रहा है. भारत सरकार के निर्णय पर आज पूरे देश में प्रथम कृषि मंत्री के सम्मान में इस पावन तिथि को कृषि दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है. केंद्र सरकार गांव, गरीब और किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रही है. किसान समृद्ध होगा तभी देश मजबूत बनेगा. लग बजट इनके लिए आयेगा.

र भाजपा राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बन गये हैं नीतीश'

ना. जदयू के प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा कि पिछले दस सालों में बिहार ये गये ऐतिहासिक विकास कार्यों और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने प्रगतिशील हस्तक्षेप के चलते नीतीश कुमार गैर भाजपा राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं. जातिवादी की पहचान लिए घूम रहे क्षेत्रीय नेताओं और सांप्रदायिक होने की पहचान लिए भाजपा नेताओं से बिल्कुल अलग नीतीश कुमार ने विकास पुरुष के रूप में अपनी शख्सियत को स्थापित किया है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के महागठबंधन ने या भाजपा के साथ जाने जैसी अफवाहों को हवा दे रहे लोगों को यह होना चाहिए कि नीतीश कुमार ने हमेशा अपनी शर्तों पर राजनीति की जपा के साथ रहकर भी नीतीश ने अपने मूल धर्मनिरपेक्ष विकासवादी को मजबूती से थामे रखा.

मे मुख्यमंत्री थे लाचार : ऊषा

भाजपा की वरिष्ठ नेत्री डॉ ऊषा विद्यार्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश अपने दल के विधायकों पर नियंत्रण नहीं रहा. उन्होंने कहा कि सदन बिहार का नेतृत्व राबड़ी देवी कर रही थी. नीतीश कुमार लाचार और रहे थे. ऊषा विद्यार्थी ने कहा कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री से ती है जब विधायक मंडल में प्रश्नोत्तर काल को बाधित ही करवाना ही क्यूं था.

र स्वैप व हैंड हेल्ड मशीन से जमा होगा शुल्क

निर्णय. प्रधान सचिव ने दिये सभी निकायों को लागू करने के निर्देश

पहली जनवरी से ऑनलाइन पास होगा मकानों का नक्शा

नागरिकों को मकानों का नक्शा पास कराने के लिए नगरपालिका कार्यालयों और बाबुओं के आगे-पीछे चक्कर नहीं लगानी पड़ेगी.

संवाददाता ▸ पटना

राज्य के सभी 141 नगर निकायों में पहली जनवरी से इ-म्युनिसिपलिटी योजना लागू हो जायेगी. शहर के नागरिकों को मकानों का नक्शा पास कराने के लिए नगरपालिका कार्यालयों और बाबुओं के आगे-पीछे चक्कर लगानी नहीं पड़ेगी. अब निकायों में सिर्फ ऑनलाइन नक्शा के लिए ही आवेदन लिया जायेगा. नक्शा पास कराने के लिए किसी तरह का ऑफलाइन आवेदन स्वीकृत नहीं किया जायेगा. पहले फेज में भवनों के नक्शा पास करने में इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है. बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार इसे निर्धारित समय सीमा के अंदर दो माह के अंदर स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया जायेगा.

नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि राज्य के नगर निकायों में इ-म्युनिसिपलिटी योजना लागू है. पर यह सभी प्रकार सेवा के लिए पूर्ण रूप से लागू नहीं की गयी है. पहली बार निकायों में नक्शा पास करने के लिए यह योजना लागू की जा रही है. इस संबंध में सभी नगर निकायों को निर्देश भी दिया जा चुका है. उन्होंने बताया कि इसके लिए स्पर द्वारा अलग से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है. भवन परमिट के लिए आवेदन के लिए सक्षम प्राधिकार को किया जायेगा. इसके लिए सभी दस्तावेजों को पीडीएफ और कैड प्रारूप में सॉफ्ट कॉपी के साथ चार प्रतियों में प्रस्तुत करना है. इसमें स्थल की चौहद्दी और उससे संलग्न भूमि, पड़ोस के पथ के संबंध में स्थल की स्थिति की साथ नगरपालिका का प्लाट संख्या तथा राजस्व भूखंड संख्या, जिस रास्ते पर भवन है उसका नाम, जिस पथ पर भवन है उस स्थल पर उसके अधीन खड़े सभी विद्यमान भवनों की सूचना, स्थल की चौहद्दी और यदि स्थल का उपविभाजन किया गया है तो आवेदक के स्वामित्व वाले भाग की और अन्य स्वामित्व वाले भागों की भी चौहद्दी, स्थल के या संलग्न भूमि के 18 मीटर की दूरी के अंतर्गत आनेवाले सभी निकटवर्ती पथ, भवन और परिसर और यदि स्थल से 15 मीटर की दूरी के अंतर्गत कोई पथ नहीं हो तो निकटतम विद्यमान पथ की जानकारी देना है. जो भवन का निर्माण कराना चाहते हैं उसमें आने के लिए पहुंच का रास्ता की जानकारी, हवा, प्रकाश की मुक्त आवाजाही तथा साफ-सफाई के प्रयोजनार्थ आवागमन सुनिश्चित करने के लिए भवन में और उसके इर्द-गिर्द छोड़े गये स्थल की लंबाई-चौड़ाई तथा खुले स्थानों का ब्योरा देना होगा. 15 मीटर से ऊंची इमारतों के लिए शैक्षणिक, सभा, औद्योगिक, भंडारण और हानिकारक व 500 मीटर से अधिक के आच्छादित जमीनी क्षेत्रफल वाले विशेष भवन की जानकारी जिसमें वाहन के घुसने तथा मोटर वाहन को भवन के चारों ओर चलाने के मार्ग की जानकारी देनी होगी.

प्रस्तावित भवन की पूरी जानकारी देनी होगी

प्रस्तावित भवन के सामने के पथ की तथा स्थल के पिछले भाग के किसी पथ की चौड़ाई, भवन की योजना के संदर्भ में उपयोग में लाये गये पैमाने तथा उत्तरी छोर की दिशा, कोई विद्यमान भौतिक विशिष्टताएं जैसे कुआं व जल निकासी, मल निकासी, जल निकासी लाइन और जलापूर्ति लाइन और वृक्षों की अवस्थिति के बारे में सूचनाएं देनी होगी. इसके साथ ही बिल्डिंग प्लान देना है. इसमें भूस्वामित्व का मूल विलेख या पट्टा का प्रमाणित प्रति, राजस्व सर्वे शीट या नगरपालिका शीट की प्रमाणित प्रति, खेसरा संख्या या दाखिल खारिज का अभिलेख देना है.

मांगा गया. अब तक 396 शिक्षकों का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने की वजह से उनका उस दिन के वेतन में कटौती की गयी है. बाकी शिक्षकों के जवाब का इंतजार किया जा रहा है. दरभंगा में अनुपस्थित सभी 186, पश्चिमी चंपारण में 49, सीतामढ़ी में 38, जमुई में 33, सहरसा में 17, किशनगंज में 12 व शेखपुरा में तीन शिक्षकों का वेतन काटा गया है. वहीं, नवादा, अररिया, अरवल, बांका, बक्सर, कैमूर, रोहतास व शिवहर के कई स्कूलों का जीविका की दीदी ने निरीक्षण किया. इन जिलों में एक भी शिक्षक गैर हाजिर नहीं मिले. मुंगेर जिले में भी 97 स्कूलों के निरीक्षण के दौरान बिना सूचना के एक शिक्षक गायब

---

556 करोड़ से घ पानी पहुंचाने पर

पटना. सरकार के सात निश्चय में शामिल हर घर नल का पानी योजना के तहत पहले साल 556 करोड़ से घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाने की योजना पर काम शुरू होगा. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत 2288 वार्ड, फ्लोराइड व आयरन ग्रस्त एक हजार टोले, आर्सेनिक ग्रस्त 96 टोले व विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण जलापूर्ति व स्वच्छता परियोजना के तहत 50 पंचायत में घर-घर नल से पानी पहुंचाना है. योजना के तहत जहां इस साल काम शुरू होना है वहां अगले साल दिसंबर से घरों में नल से पानी मिलना शुरू हो जायेगा. पीएचइडी

गर्भाशय निकासी कांड में नहीं

27 पीआइओ पर 25-25